बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 90 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 16 जनवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

पुलिस और लॉरेंस गैंग के शूटर्स के बीच मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली, दो गिरफ्तार

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों के बीच गुरुवार सुबह मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गैंग के दो शूटर्स को गिरफ्तार किया है। यह दोनों शूटर दिल्ली के पश्चिम विहार और विनोद नगर इलाकों में हुई गोलीबारी की घटनाओं में शामिल थे। मुठभेड़ के दौरान एक शूटर के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, दूसरा शूटर नाबालिग बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू कर दी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। यह गिरफ्तारी दिल्ली में अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 12 और 13 जनवरी को पूर्वी दिल्ली के पश्चिमी विनोद नगर और पश्चिमी विहार में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी।

दिल्ली को मिलेंगे चार नए बड़े अस्पताल, 3200 से ज्यादा बेड होंगे उपलब्ध, जुलाई 2026 तक तैयार

नई दिल्ली ।

दिल्ली सरकार इस साल राजधानी के लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है. सरकार सिरसपुर, मादीपुर, हस्तसाल और वालापुरी में चार नए बड़े सरकारी अस्पताल शुरू करने जा रही है.

इन अस्पतालों के शुरू होने से दिल्ली में इलाज की सुविधाएं बढ़ेंगी और बड़े अस्पतालों पर मरीजों का बोझ कम होगा. इन चारों अस्पतालों में कुल 3200 से अधिक बेड उपलब्ध कराए जाएंगे. सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इन अस्पतालों का निर्माण कार्य 65 से 85 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है. लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को निर्देश दिए गए हैं कि काम तेजी से पूरा किया जाए. अधिकतर अस्पतालों को जुलाई 2026 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि हस्तसाल अस्पताल सितंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है.

कहां बन रहे हैं नए अस्पताल

ये चारों अस्पताल पश्चिमी और बाहरी दिल्ली के इलाकों में बन रहे हैं

1.सिरसपुर अस्पताल- बाहरी दिल्ली में बन रहा है, जिससे बादली, बवाना, स्वरूप नगर, नंगली पूना और खेड़ा कलां जैसे इलाकों के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा.

2.मादीपुर, हस्तसाल और वालापुरी अस्पताल- पश्चिमी दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी सुविधा बनेंगे.

फर्नीचर, मशीनें और स्टाफ भर्ती की तैयारी शुरू

अधिकारियों ने बताया कि अस्पतालों में इलाज के साथ-साथ जरूरी फर्नीचर, मशीनें और स्टाफ भर्ती की तैयारी भी शुरू कर दी गई है, ताकि अस्पताल शुरू होते ही मरीजों को पूरा इलाज मिल सके. इन अस्पतालों के चालू होने से दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम होगा. फिलहाल पश्चिमी दिल्ली के लाखों लोग इलाज के लिए डीडीयू अस्पताल पर निर्भर हैं, जहां अक्सर बेड की कमी रहती है.

परियोजना में देरी पर सख्त रुख

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि करीब एक हजार करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद पिछली सरकार इन अस्पतालों को समय पर पूरा नहीं कर सकी. उन्होंने साफ कहा कि विकास कार्यों में देरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई है.

देरी से बढ़ी लागत

पीडब्ल्यूडी सूत्रों के मुताबिक, परियोजनाओं में देरी की वजह से इन अस्पतालों की लागत काफी बढ़ गई है. उदाहरण के तौर पर, वालापुरी और मादीपुर अस्पताल का शुरुआती टेंडर करीब 269 करोड़ रुपये का था, लेकिन अब इनकी लागत बढ़कर लगभग 472 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है.

स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करेंगे नए अस्पताल

दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ रही है और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है. कोरोना काल के बाद से स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत और यादा महसूस की गई. ऐसे में ये चार नए अस्पताल दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे और आम लोगों को सस्ता और बेहतर इलाज मिल सकेगा.

लोकतंत्र को लेकर भारत ने दुनिया को गलत साबित किया, सीएसपीओसी में बोले पीएम मोदी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत हर वैश्विक मंच पर वैश्विक दक्षिण के हितों की पुरजोर वकालत कर रहा है, और वैश्विक एजेंडा के केंद्र में इस क्षेत्र की चिंताओं को लगातार प्राथमिकता देने के अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया। संसद भवन में राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन (सीएसपीओसी), 2026 में अपने संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री ने वैश्विक दक्षिण के एजेंडे को आगे बढ़ाने में भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उसके नवाचारों से पूरे वैश्विक दक्षिण और राष्ट्रमंडल देशों को लाभ मिले, और साथ ही सहयोगी देशों के लिए ओपन-सोर्स प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए भी

प्रतिबद्ध है ताकि वे भारत में लागू की जा रही प्रणालियों के समान प्रणालियाँ विकसित कर सकें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हर वैश्विक मंच पर वैश्विक दक्षिण के हितों की पुरजोर वकालत कर रहा है। जी20 की अध्यक्षता के दौरान भी भारत ने वैश्विक एजेंडा के केंद्र में वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को रखा है। भारत का निरंतर प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि हम जो भी नवाचार करें, उससे पूरे वैश्विक दक्षिण और राष्ट्रमंडल देशों को लाभ मिले।

हम ओपन-सोर्स तकनीकी प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं ताकि वैश्विक दक्षिण में हमारे सहयोगी देश भी भारत जैसी प्रणालियाँ विकसित कर सकें। प्रधानमंत्री ने भारतीय लोकतंत्र के समावेशी स्वरूप पर जोर देते हुए कहा कि इसकी पहचान अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता से होती है। जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर, हम समावेशी रूप से काम कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी पीछे न छूटे।

इसी प्रतिबद्धता के कारण भारत ने हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। भारत में लोकतंत्र वास्तव में परिणाम देता है। भारत में लोकतंत्र का अर्थ है अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाना। उन्होंने आगे कहा, हम बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। और जन कल्याण की इसी भावना के कारण पिछले कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।

आग की वॉर्निंग! 190 यात्रियों को लेकर एक घंटे तक हवा में घूमा प्लेन, फिर दिल्ली वापस लौटा एयर इंडिया का विमान

नई दिल्ली।

राजधानी दिल्ली से सिंगापुर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी दिक्कत आ गई, जिस वजह से फ्लाइट को दिल्ली वापस लौटना पड़ा। इस फ्लाइट में 190 लोग सवार थे। सूत्रों के मुताबिक, इस सर्विस को ऑपरेट करने वाले ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट में टेक्निकल दिक्कत आ गई थी।

सूत्रों ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि APU (ऑक्सिलरी पावर यूनिट) में आग लगने की वॉर्निंग मिली थी, जिसके बाद एयरक्राफ्ट करीब एक घंटे हवा में रहने के बाद दिल्ली लौट आया। इसके बाद यात्रियों को दूसरे एयरक्राफ्ट से सिंगापुर भेजा गया। वहीं, एयर इंडिया के प्रवक्ता से संपर्क किया गया, तो उन्होंने बताया कि 14 जनवरी को दिल्ली से सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट AI 2380 के

ऑपरेटिंग क्रू ने एक शक वाली टेक्निकल दिक्कत की वजह से टेकऑफ के तुरंत बाद एहतियात के तौर पर दिल्ली लौटने का फैसला किया। प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, एयरक्राफ्ट दिल्ली में सेफ लैंड हो गया। दिल्ली में हमारी ग्राउंड टीमों ने यात्रियों को सभी जरूरी मदद दी और फ्लाइट दूसरे एयरक्राफ्ट से सिंगापुर के लिए रवाना हो गई। प्रवक्ता ने इस अचानक हुई स्थिति की वजह से यात्रियों को हुई परेशानी के लिए अफसोस भी जताया।

पश्चिम बंगाल में पुलिस बनी ममता का औजार? बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सरकार को घेरा

नई दिल्ली । भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कोलकाता स्थित राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पीएसी के कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के दौरान कथित हस्तक्षेप को लेकर आलोचना की है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए, भाजपा के वरिष्ठ नेता रवि शंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री के आई-पीएसी कार्यालय जाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह न तो टीएमसी का कार्यालय है और न ही किसी पार्टी नेता का निवास स्थान। प्रसाद ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर कल पुलिस की मौजूदगी में हमला किया गया। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के प्रयासों के बावजूद कोई मामला दर्ज नहीं किया गया और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की पूरी पुलिस व्यवस्था मुख्यमंत्री के हाथों का औजार बन गई है, और कहा कि राज्य में कानून प्रवर्तन प्रणाली का दुरुपयोग असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं, ने आई-पीएसी कार्यालय और इसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर ईडी की जांच और तलाशी अभियान में हस्तक्षेप किया। सुनवाई से पहले, ईडी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को निलंबित करने की मांग की है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने जैन के आवास पर तलाशी में बाधा डाली। इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने एक आपत्ति दर्ज कराई है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि राजनीतिक सलाहकार कार्यालय पर एजेंसी की छापेमारी के संबंध में उसकी सुनवाई के बिना कोई आदेश पारित न किया जाए।

बेशर्मी की हद्द है! स्वाति मालीवाल ने अकाल तख्त पर कथित टिप्पणी को लेकर भगवंत मान पर साधा निशाना

नई दिल्ली ।राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर श्री अकाल तख्त के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर जमकर हमला बोला। मान पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने दावा किया कि वे धार्मिक और सरकारी स्थलों पर जाने से पहले शराब पीते हैं और अपनी सरकार में चोरों और बदमाशों को जगह देते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि मान ऑस्ट्रेलिया में लाखों रुपये छिपा रहे हैं। एक्स पर पोस्ट में सांसद मालीवाल ने लिखा कि करोड़ों रुपये ऑस्ट्रेलिया में ठिकाने लगाके, शराब पीकर गुरुद्वारा-मंदिर-सरकारी मीटिंग-संसद में जाने वाले। चोरों-गुंडों को अपनी सरकार में जगह देने वाले एक शख्स, पवित्र श्री अकाल तख्त पर घटिया बयान और आरोप लगा रहे है। घोर कलयुग है। बेशर्मी की हद्द है! पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज सिख परंपराओं पर कथित टिप्पणियों के सिलसिले में श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय के समक्ष पेश हुए और उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ फैलाई जा रही अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। सचिवालय के समक्ष पेश होने के बाद उन्होंने कहा कि सिंह साहिब का फैसला उन्हें बता दिया जाएगा और वे सचिवालय के आगामी निर्णय का सम्मान करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी टिप्पणी का वीडियो «फर्जी» है और उन्होंने इसे फॉरेंसिक प्रयोगशाला में जांच कराने का प्रस्ताव रखा। मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ मिली सभी शिकायतों के जवाब में मैंने श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष अपना पक्ष रखा है। मैंने अकाल तख्त साहिब के समक्ष लिखित प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। मैंने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर चल रही वे अफवाहें कि भगवंत मान श्री अकाल तख्त साहिब को चुनौती दे रहे हैं, झूठी हैं। अकाल तख्त साहिब के समक्ष ऐसा करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। सिंह साहब का निर्णय मुझे सूचित किया जाएगा। सिंह साहब के निर्णय का सम्मान किया जाएगा... मैंने उन्हें बताया कि वीडियो फर्जी है और इसकी जांच किसी भी फॉरेंसिक प्रयोगशाला में कराई जा सकती है।

गणतंत्र दिवस के चलते दिल्ली अलर्ट पर, एम्स पार्किंग में अनदेखा खतरा... आशंका के और भी पहलू

नई दिल्ली ।

एक तरफ राजधानी में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की जा रही है। दूसरी ओर एम्स दिल्ली जैसे नामचीन अस्पताल की पार्किंग में लावारिस वाहन धूल फांक रहे हैं। इनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। इससे अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पार्किंग के हालात को लेकर अमर उजाला के संवाददाता ने खुद मौके पर जाकर बुधवार को जायजा लिया। एम्स में उपचार के लिए ओपीडी में आने वाले मरीजों और तीमारदारों के लिए बेसमेंट पार्किंग नंबर तीन में वाहनों के पार्क करने की व्यवस्था है। पार्किंग के पिलर नंबर यूबी-3/6 के सामने लावारिस हालत में दोपहिया वाहन पार्क हैं। इसमें दो स्कूटी और एक बाइक शामिल है। वाहनों पर धूल का गुबार जमा हो रखा है। इसमें बाइक के पीछे के हिस्से में नंबर प्लेट तक गायब है। इसी तरह पार्किंग शुल्क के काउंटर के नजदीक भी अलग-अलग रायों के पंजीकृत दोपहिया वाहन लावारिस हालत में खड़े हैं। इसमें कुछ बाइक के टायरों की हवा तक निकली है।

ऐसी ही तस्वीर पार्किंग के दूसरे हिस्से में भी जगह-जगह बनी हुई है जिसमें गाड़ियां भी लावारिस हालत में खड़ी हैं। सबसे यादा चिंताजनक बात यह है कि पार्किंग में प्रवेश के दौरान वाहनों की कोई जांच नहीं होती है।

परिसर में जमा है कबाड़

पार्किंग परिसर में केंद्र सरकार के स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। परिसर में जगह-जगह कबाड़ जमा हो रखा है। टूटी-फूटी अलमारी, पत्थर, लोहे की जाली, कुर्सी, मेज, डक्टिंग वेंटिलेशन इधर-उधर पड़े हैं। हैरानी वाली बात यह है जिस जगह से दोपहिया वाहनों की निकासी का रास्ता है, उसके बीच में भी बेकार सामान पड़ा है। इससे दोपहिया वाहन चालकों को निकलने में मुश्किल होती है। दीवारों पर धूल जमी और जाले लगे हुए है। पार्किंग के फर्श पर धूल जमा हो रखी है। परिसर में पानी की निकासी वाली नाली पर लगी लोहे की जाली अंदर धंस रही है।

खुले पड़े हैं बिजली के स्विच बोर्ड

पार्किंग में बिजली के स्विच बोर्ड भी खस्ता हालत में हैं। पिलर नंबर यूबी-3/4 में लगा बिजली के स्विच बोर्ड खुला है। बोर्ड से स्विच बाहर निकले लटके पड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि पिलर से सटकर दोपहिया वाहन भी पार्क होते हैं। जब पार्किंग से निकलर सीढ़ियों के रास्ते से सबसे ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ेंगे तो दीवार पर लगे बिजली का बोर्ड स्विच बाहर निकला पड़ा दिखेगा। पार्किंग के बदतर हालात एम्स मीडिया सेल प्रमुख डॉ. रीमा दादा के संज्ञान में लाने पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में कार्रवाई के लिए सीएसओ और फैकल्टी इंचार्ज को सूचित कर दिया है।

अमेरिका के कदम द्विपक्षी रिश्तों को नुकसान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सनकी रवैये को देखते हुए कोई भी अनुमान लगाना मुश्किल है। पिछले कुछ दिनों से वे लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं लेकिन पिछले दो दिनों में अमेरिका का जो रुख देखने को मिला उससे ऐसा लगता है कि दिल्ली और वाशिंगटन के बीच कूटनयिक सम्पर्क फिर से कायम हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता को लेकर सक्रियता नजर आ रही है। पहले भारत में नियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच दोस्ती बहुत मजबूत है और दोनों के रिश्ते सबसे ऊंचे राजनीतिक स्तर पर बहुत मजबूती से टिके हुए हैं। असली दोस्ती में कभी-कभी मतभेद हो जाते हैं लेकिन वे दोनों मिलकर मतभेदों को अच्छे से सुलझा लेते हैं। उन्होंने चौकाने वाला बयान यह भी दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप जल्द भारत आ सकते हैं। अमेरिका के लिए भारत से ज्यादा अहम साझेदार कोई नहीं है। अब एक अच्छी खबर यह है कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेशी मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो में फोन पर बातचीत हुई। दोनों ने द्विपक्षीय व्यापार वार्ता दुर्लभ खनिजों, रक्षा, परमाणु सहयोग, ऊर्जा और अगले महीने होने वाली संभावित बैठक पर चर्चा की। इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि दोनों देशों में व्यापार वार्ता में काफी प्रगति हो चुकी है लेकिन अन्य विषयों के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। मार्को रूबियो ने हाल ही में भारत द्वारा परमाणु ऊर्जा दोहन एवं विकास विधेयक यानि परमाणु ऊर्जा कानून पारित करने पर भारत की सराहना की और कहा कि इससे अमेरिकी कम्पनियों के लिए अवसरों का विस्तार करने और साझा ऊर्जा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने अपने बयान में अमेरिका द्वारा पैक्स सिलिका रणनीतिक पहल के लिए भारत को आमंत्रित करने की बात कही थी जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पैक्स सिलिका एक ऐसी पहल है जो चीन का मुकाबला करने के लिए शुरू की गई है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा स्रोतों से लेकर उन्नत विनिर्माण, सभी कंडक्टर, एआई विकास और लॉजिस्टिक तक एक सुरक्षित समृद्ध और नवाचार संचालित सिलिकान आपूर्ति शृंखला का निर्माण करना है। इस पहल में जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और इजराइल पहले ही शामिल हो चुके हैं। भारत को इस समूह में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। विदेश मंत्री एस.जयशंकर और मार्को रूबियो में पिछले वर्ष भी मुलाकातें होती रही हैं। भारत ने सितंबर 2025 में रूस से तेल आयात कम कर दिया है जिससे वाशिंगटन को यह संकेत मिला है कि अमेरिका को 25 प्रतिशत दंडात्मक टैरिफ हटा देना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि 25 प्रतिशत टैरिफ जुर्माने की छूट एक ऐसा कदम है जो दोनों पक्षों के बीच संबंधों में तनाव को कम कर सकता है, जबकि दोनों पक्ष शेष 25 प्रतिशत कम टैरिफ प्राप्त करने के लिए व्यापार समझौते पर बातचीत जारी रखते हैं। इस मामले में तात्कालिकता का भाव ऐसे समय में भी सामने आया है जब भारत और यूरोपीय संघ अपने स्वयं के व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड और समारोहों के लिए मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय संघ के नेताओं के भारत आने और उसके बाद भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले इसे अंतिम रूप दे दिया जाए। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि रूस से तेल को परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। ट्रंप ने तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फरमान जारी कर रखा है। सच्चाई तो यह है कि अमेरिका को आज भारत की बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जरूरत सिर्फ भारत को ही है। दोनों ही देशों ने द्विपक्षीय कारोबार को लेकर बड़ा लक्ष्य बनाया है। भारत और अमेरिका ने साल 2030 तक अपने द्विपक्षीय कारोबार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य बनाया है। व्यापार के अंतर को कम करने के लिए भारत ने अमेरिका से वादा किया है कि वह एनर्जी और रक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाएगा। भारत ने यह वादा तब किया है, जबकि पिछले साल दोनों के बीच हुई व्यापार वार्ता अभी तक बेनतीजा रही है। ट्रंप के टैरिफ के प्रभाव से बचने के लिए भारत लगातार उपाय कर रहा है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत आए थे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद दोनों देशों में रक्षा और सेमीकंडक्टर समेत महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों नेताओं ने भू-राजनीतिक उथल-पुथल और खासतौर पर ट्रंप के मनमाने रवैये पर चर्चा भी की। भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का रोड मैप तैयार किया। अमेरिकी दबाव के बावजूद जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। भारत ने खाड़ी देशों और कई अन्य देशों के साथ व्यापार को प्राथमिकता दी है। भारत वाशिंगटन तक यह संदेश पहुंचाने में सफल रहा है कि अमेरिका के कदम द्विपक्षी रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इस तरह अमेरिका भारत के रूप में एक अच्छा मित्र खो देगा। युद्ध से लेकर तेल तक ट्रंप हर दिन कोई न कोई नया दावा कर देते हैं। ट्रंप की बातें पारम्परिक कूटनीतिक भाषा से अलग और असामान्य हैं। ट्रंप के फरमानों से नाटो और यूरोपीय देश भी परेशान हो चुके हैं और ट्रंप अपना भरोसा गंवाते जा रहे हैं। दबाव कितना भी क्यों न हो ट्रंप की तानाशाही को कोई इतना क्यों सहेगा। ट्रंप अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए भी ऊटपटांग बातें कर रहे हैं। तमाम जटिलताओं के बावजूद भारत-अमेरिका में समग्र ट्रेड डील पर सहमति बनती है तो यह दोनों देशों के लिए बेहतर होगा।

ट्रम्प की लाठी से सब डरते है

स्कूल में पढ़ा करते थे कि 'माइट इज राइट', जिसका हिन्दी अनुवाद 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' बताया गया। जो ताकतवर है वह कुछ भी कर सकता है। इसी सिद्धांत का नया संस्करण हम नए वर्ष में देख रहे हैं। अमेरिका ने अपने सैनिक भेज कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तथा उनकी पत्नी को उनकी राजधानी कराकस में अपने महल के बेडरूम से उठा लिया और उन्हें न्यूयार्क ले आए जहां हथकड़ी लगे निकोलस मादुरो को अदालत के सामने पेश किया गया। उन पर आरोप है कि वह 'नार्को-टैरिज्म' अर्थात नशे के आतंकवाद में संलिप्त है। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि अब वह वेनेजुएला को चलाएंगे और उसके विशाल तेल भंडार जो दुनिया में सबसे अधिक है, को सम्भालेंगे। वेनेजुएला का तेल भंडार 303 अरब बैरल है जो तेल को वर्तमान कीमतों के अनुसार 17 ट्रिलियन डालर का है। ट्रम्प का कहना है कि यह सब हमारा है। लाठी (सेना) भी, (भैंस) वेनेजुएला भी, और अब तेल भी। बाकी दुनिया, भारत समेत, चुपचाप यह उठी प्रतिक्रिया जता कर बैठ गई है। आखिर ट्रम्प की लाठी से सब डरते हैं। कोई उससे पंगा नहीं लेना चाहता। विशेषज्ञ सी. उदय भास्कर ने इसे 'रणनीतिक बुज़दिली' कहा है। अमेरिका की ऐसी एक पक्षीय कार्रवाई दुनिया ने पहले भी देखी है। जनवरी 1990 में वह पनामा के सैनिक लीडर मैनुअल नौरीगा जिसे कभी अमेरिका का आदमी समझा जाता था, को वहां से उठा लाए थे।

उस पर भी नशे का धंधा करने का आरोप था। उसे अमेरिका में 40 साल की सजा दी गई थी। मई 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान की सैनिक छावनी एबटाबाद में घुस कर ओसामा बिन लादेन को मार दिया था और उसकी लाश समुद्र में फेंक दी थी। इन दो घटनाओं और वेनेजुएला की घटना में अंतर है। तब अमेरिका ने दुनिया को समझाने की कोशिश की थी कि कार्रवाई क्यों की गई। औचित्य समझाया था। जब इराक में कार्रवाई की गई तो बताया गया कि सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं, चाहे निकला कुछ नहीं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाते हुए ट्रम्प की सरकार ने कोई स्पष्टीकरण देने की ज़हमत नहीं उठाई। ट्रम्प ने कहा भी है कि वह किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून में विश्वास नहीं रखते। उनका विश्वास केवल «अपनी विचारधारा और अपनी अंतरात्मा में है»। अर्थात हम अब साम्राज्यवाद का नया रूप देख रहे हैं। केवल रणनीतिक मामलों में ही नहीं, आर्थिक मामलों में भी दिख रहा है। हम पर भी 50% टैरिफ लगाया हुआ है और 500% लगाने की धमकी दी जा रही है। द इकानमिस्ट ने लिखा है कि, «डोनाल्ड ट्रम्प येजाना प्रदर्शित कर रहे हैं कि दुनिया में जो मायने रखता है वह अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं, नंगी ताकत है»। निकोलस मादुरो एक क्रूर तानाशाह था जो पिछले 13 वर्ष से चुनावी धांधली,भ्रष्टाचार, मानवीय अधिकारों के घोर उल्लंघन और सैंसरशिप के द्वारा सत्ता पर काबिज था। आर्थिक तंगी के कारण लोग उसके खिलाफ थे। अलोकप्रियता का यह हाल था कि अपनी सुरक्षा के आंतरिक घेरे में उसने अपनी सेना के अधिकारी नहीं, बल्कि क्यूबा के कमांडो रखे हुए थे जो सब अमेरिकी कार्रवाई में मारे गए। पर यह सारी कहानी मादुरो की तानाशाही की नहीं है, अमेरिका की एकतरफीय कार्रवाई की है। वेनेजुएला अमेरिका पर हमला करने की नहीं सोच रहा था जिसका जवाब, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, अमेरिका दे सकता था। ऐसा कुछ नहीं था। मादुरो का क्या करना है यह वेनेजुएला के लोगों पर छोड़ दिया जाना चाहिए था, पर एक नई खतरनाक मिसाल कायम कर दी गई है। एक बार अंतर्राष्ट्रीय नियमों की परवाह बंद हो गई तो और भी इस रास्ते पर चल सकते हैं। पर यह डोनाल्ड ट्रम्प का अमेरिका है। कराकस पर नाइट स्ट्राइक अमेरिका की ताकत का नंगा प्रदर्शन है और यह भी बताता है कि अमेरिका जहां समझता है कि उसके हित है, वहां ताकत का इस्तेमाल करने को तैयार है। संयुक्त राष्ट्र तो पहले ही अशक्त बन चुका है। डोनाल्ड ट्रम्प को चिन्ता नहीं कि बाकी दुनिया क्या कहती है। वह केवल अमेरिका को अपनी सोच के मुताबिक 'ग्रेट' बनाने में लगे हैं। यह होता है या नहीं, या अमेरिका अपना प्रभाव खो देता है, यह समय ही बताएगा। बुद्धिजीवी फरीद जकारिया का कहना है कि ऐसी कार्रवाइयों से अमेरिका «अधिक ताकतवर, पर अधिक अकेला पड़ जाएगा»। अमेरिका को कभी आजादी और लोकतंत्र का ध्वजवाहक समझा जाता था, पर आज उसका व्यवहार पुतिन के रूस की तरह है। वेनेजुएला बहुत समय से चीन और रूस के नजदीक जा रहा था। चीन को विशेष धक्का पहुंचा है। वह दक्षिण अमेरिका के देशों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था कि अमेरिका ने 'नो एंट्री' का बोर्ड लगा दिया। चीन वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा आयातक है। चीन ने उस क्षेत्र में बहुत निवेश किया है जो अमेरिका अपने प्रभाव का क्षेत्र समझता है। यह रुक जाएगा, पर चीन अपने आसपास के क्षेत्र में और सक्रिय हो सकता है। पुराने स्टाइल के साम्राज्यवाद की वापसी से क्या रूस और चीन को अपने पड़ोस में और दखल का मौका मिल जाएगा? चीन ताइवान या दक्षिण चीन सागर में और दुस्साहसी हो जाएगा? भारत को भी इस में दिलचस्पी होगी कि चीन आगे क्या करता है क्योंकि हमारे साथ भी सीमा विवाद है। भारत को मादुरो में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उसकी दुर्गति को हम निसंकोच चुपचाप नहीं देखना चाहते। अभी तक चीन और रूस की प्रतिक्रिया संयत रही है। वह स्थिति का जायजा ले रहे हैं। ताइवान पर चीन की कार्रवाई बहुत कुछ सैनिक क्षमता, सफलता की सम्भावना, आर्थिक नुकसान तथा बाहरी दखल के आकलन पर निर्भर करेगी। चीन अमेरिका की तरह बेधड़क नहीं है और ताइवान वेनेजुएला की तरह बेबस नहीं है। जो देश सबसे पहले ट्रम्प के निशाने पर हो सकता है वह ईरान है जहां पहले ही जमीन तैयार हो चुकी है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमैनी के शासन के खिलाफ देशभर में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। कई सौ लोग मारे जा चुके हैं।

सम्पादकीय...

प्रतिनिधि की जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट फिलहाल आवारा कुत्तों के मुद्दे पर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। जहां एक तरफ याचिकाएं आवारा कुत्तों के खतरे से निपटने के लिए अधिकारियों द्वारा सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ याचिकाएं जानवरों के अधिकारों के पक्ष में हैं। यह एक साल में चौथी बार है, जब सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर विचार कर रहा है। पिछले साल कोर्ट की एक डिवीजन बैंच ने दिल्ली सरकार को नगर निगम क्षेत्रों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें इंसानी बस्तियों से दूर डॉग शैल्टर में भेजने का आदेश देकर हलचल मचा दी थी। काफी हंगामे के बाद, सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बैंच ने इस आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि कोर्ट के पिछले आदेश को लागू करना संभव नहीं है। इसके बाद, एक और बैंच ने फैसले को पलट दिया और शैक्षणिक संस्थानों, खेल परिसरों, अस्पतालों और बाजारों जैसे सार्वजनिक स्थानों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया। ताजा सुनवाई, जो कोर्ट ने खुद शुरू की थी, कई दिनों से चल रही है तथा कुछ और दिनों तक जारी रहने की संभावना है। निस्संदेह यह एक गंभीर मुद्दा है और अधिकारी एक व्यवहार्य और प्रभावी समाधान खोजने में विफल रहे हैं। नैशनल सैंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एन.सी.डी.सी.) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा था कि 2024 में कुत्तों के काटने के कुल मामले 37,17,336 थे, जबकि 'संदिग्ध मानव रैबीज से होने वाली मौतों' की कुल संख्या 54 थी। इसमें पालतू कुत्तों के काटने के मामले भी शामिल हैं, लेकिन ऐसे मामले बहुत कम हैं। यह एक सच्चाई है कि बहुत से लोग, खासकर बुजुर्ग, कुत्तों के झुंड द्वारा हमला किए जाने के डर से टहलने के लिए बाहर जाने से हिचकिचाते हैं। ऐसे हमलों की संख्या, खासकर बच्चों पर, पूरे देश में बढ़ रही है। एक याचिका पर जवाब देते हुए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को आवारा कुत्तों के काटने के मामलों में पीड़ितों को 10,000 रुपए की दर से मुआवजा देने का निर्देश दिया था। इसी तरह पालतू कुत्तों के मालिकों को भी पीड़ितों को उसी दर से मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। हालांकि यह एक थकाऊ प्रक्रिया है और अब तक बहुत कम लोगों ने दावा किया है। दूसरी ओर, कुत्ता प्रेमियों को आवारा कुत्तों को खाने की चीजें बांटते देखना आम बात है। कुछ लोग ऐसा हर दिन करते हैं और कुत्तों के झुंड उनके आने का इंतजार करते हैं। सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स, जिसका गठन पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने किया था, जानवरों के खिलाफ अपराधों के मामलों को सक्रिय रूप से उठा रही है। कुछ लोग आवारा कुत्तों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी और कुत्ते के काटने के मामलों के लिए उन्हें और संगठन को भी दोषी ठहराते हैं। एनिमल बर्थ कंट्रोल (ए.बी.सी.) रूल्स, 2023, जिसमें 'आवारा कुत्तों' की बजाय 'कम्युनिटी एनिमल्स' शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इन जानवरों को खाना खिलाने का प्रावधान करता है। 'यह रैजिडैंट वैल्फेयर एसोसिएशन या अपार्टमैंट ओनर्स एसोसिएशन या लोकल बॉडी के प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होगी कि वे दया भाव से कम्युनिटी एनिमल्स को खाना खिलाने के लिए जरूरी इंतजाम करें'।

काशी-तमिल संगमम एक अनूठा प्रयास

भारतवर्ष की आध्यात्मिक समृद्धि पर बल देते हुए उन्होंने बताया कि कैसे इस तरह के मंच राष्ट्रीय एकता को और अधिक सुदृढ़ करते हैं। काशी-तमिल संगमम का बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिला है। इसके जरिए जहां सांस्कृतिक चेतना को मजबूती मिली है, वहीं शैक्षिक विमर्श और जनसंवाद को भी काफी बढ़ावा मिला है। इससे हमारी संस्कृतियों के बीच संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। इस मंच ने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को आगे बढ़ाया है, इसलिए आने वाले समय में हम इस आयोजन को और वाइब्रेंट बनाने वाले हैं। ये वो भावना है जो शताब्दियों से हमारे पर्व-त्योहार, साहित्य, संगीत, कला, खान-पान, वास्तुकला और ज्ञान-पद्धतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। वर्ष का यह समय हर देशवासी के लिए बहुत ही पावन माना जाता है।

कुछ दिन पहले ही मुझे सोमनाथ की पवित्र भूमि पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेने का सुअवसर मिला। इस पर्व को हम वर्ष 1026 में सोमनाथ पर हुए पहले आक्रमण के एक हजार साल पूरे होने पर मना रहे हैं। इस क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने-कोने से लोग सोमनाथ पहुंचे। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतवर्ष के लोग जहां अपने इतिहास और संस्कृति से गहराई से जुड़े हैं, वहीं कभी हार ना मानने वाला साहस भी उनके जीवन की एक बड़ी विशेषता है। यही भावना उन्हें एक साथ जोड़ती भी है। इस कार्यक्रम के दौरान मेरी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से भी हुई जो इससे पहले सौराष्ट्र-तमिल संगमम के दौरान सोमनाथ आए थे और इससे पहले काशी-तमिल संगमम के समय काशी भी गए थे। ऐसे मंचों को लेकर उनकी सकारात्मक सोच ने मुझे बहुत प्रभावित किया। इसलिए मैंने तय किया कि क्यों ना इस विषय पर अपने कुछ विचार साझा करूं। 'मन की बात' के एक एपिसोड के दौरान मैंने कहा था कि अपने जीवन में तमिल भाषा ना सीख पाने का मुझे बहुत दुख है। यह हमारा सौभाग्य है कि बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार तमिल संस्कृति को देश में और लोकप्रिय बनाने में निरंतर जुटी हुई है। यह 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को और सशक्त बनाने वाला है। हमारी संस्कृति में संगम का बहुत महत्व है। इस पहलू से भी काशी-तमिल संगमम एक अनूठा प्रयास है। इसमें जहां भारत की विविध परंपराओं के बीच अद्भुत सामंजस्य दिखता है, वहीं यह भी पता चलता है कि कैसे हम एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करते हैं। काशी तमिल संगमम के आयोजन के लिए काशी सबसे उपयुक्त स्थान कहा जा सकता है। यह वही काशी है जो अनादि काल से हमारी सभ्यता की धुरी बनी हुई है। यहां हजारों वर्षों से लोग ज्ञान, जीवन के अर्थ और मोक्ष की खोज में आते रहे हैं। काशी का तमिल समाज और संस्कृति से अत्यंत गहरा नाता रहा है। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो तमिलनाडु में रामेश्वरम तीर्थ है। तमिलनाडु की तेनकासी को दक्षिण की काशी या दक्षिण काशी कहा जाता है। पूज्य कुमारगुरुपर स्वामीजी ने अपनी विद्वता और आध्यात्म परंपरा के माध्यम से काशी और तमिलनाडु के बीच एक सशक्त और स्थायी संबंध स्थापित किया था। तमिलनाडु के महान सपूत महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी को भी काशी में बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक जागरण का अद्भुत अवसर दिखा।

यहीं उनका राष्ट्रवाद और प्रबल हुआ, साथ ही उनकी कविताओं को एक नई धार मिली। यहीं पर स्वतंत्र और अखंड भारत की उनकी संकल्पना को एक स्पष्ट दिशा मिली। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो काशी और तमिलनाडु के बीच गहरे आत्मीय संबंध को दर्शाते हैं। वर्ष 2022 में वाराणसी की धरती पर काशी-तमिल संगमम की शुरुआत हुई थी। मुझे इसके उद्घाटन समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला था। तब तमिलनाडु से आए लेखकों, विद्यार्थियों, कलाकारों, विद्वानों, किसानों और अतिथियों ने काशी के साथ-साथ प्रयागराज और अयोध्या के दर्शन भी किए थे। इसके बाद के आयोजनों में इस पहल को और विस्तार दिया गया। इसका उद्देश्य यह था कि संगमम में समय-समय पर नए विषय जोड़े जाएं, नए और रचनात्मक तरीके अपनाए जाएं और इसमें लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो। प्रयास यह था कि ये आयोजन अपनी मूल भावना से जुड़े रहकर भी निरंतर आगे बढ़ता रहे। वर्ष 2023 के दूसरे आयोजन में टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया, ताकि यह सुनिश्चित हो कि भाषा इसमें बाधा ना बने। इसके तीसरे संस्करण में इंडियन नॉलेज सिस्टम पर विशेष फोकस रखा गया। इसके साथ ही शैक्षिक संवादों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, प्रदर्शनियों और संवाद सत्रों में लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। हजारों लोग इनका हिस्सा बने। काशी-तमिल संगमम का चौथा संस्करण 2 दिसंबर, 2025 को आरंभ हुआ। इस बार की थीम बहुत रोचक थी- तमिल करकलम् यानि तमिल सीखें.। इससे काशी और दूसरी जगहों के लोगों को खूबसूरत तमिल भाषा सीखने का एक अनूठा अवसर मिला। तमिलनाडु से आए शिक्षकों ने काशी के विद्यार्थियों के लिए इसे अविस्मरणीय बना दिया। इस बार कई और विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। प्राचीन तमिल साहित्य ग्रंथ तोलकाप्पियम का चार भारतीय और छह विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। तेनकासी से काशी तक पहुंची एक विशेष व्हीकल एक्सपेडिशन भी देखने को मिली। इसके अलावा काशी में स्वास्थ्य शिविरों और डिजिटल लिट्रेसी कैंप के आयोजन के साथ ही कई और सराहनीय प्रयास भी किए गए। इस अभियान में सांस्कृतिक एकता के संदेश का प्रसार करने वाले पांड्य वंश के महान राजा आदि वीर पराक्रम पांडियन जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूरे आयोजन के दौरान नमो घाट पर प्रदर्शनियां लगाई गईं, बीएचयू में शैक्षणिक सत्र का आयोजन हुआ, साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। काशी-तमिल संगमम में इस बार जिस चीज ने मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता दी, वो हमारे युवा साथियों का उत्साह है। इससे अपनी जड़ों से और अधिक जुड़े रहने के उनके पैशन का पता चलता है।

उनके लिए ये एक ऐसा अद्भुत मंच है, जहां वे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। संगमम के अलावा काशी की यात्रा भी यादगार बने, इसके लिए विशेष प्रयास किए गए। भारतीय रेल ने लोगों को तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश ले जाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाईं। इस दौरान कई रेलवे स्टेशनों पर, विशेषकर तमिलनाडु में उनका खूब उत्साह बढ़ाया गया। सुंदर गीतों और आपसी चर्चाओं से ये सफर और आनंददायक बन गया। यहां मैं काशी और उत्तर प्रदेश के अपने भाइयों और बहनों की सराहना करना चाहूंगा, जिन्होंने काशी-तमिल संगमम को विशेष बनाने में अपना अद्भुत योगदान दिया है। उन्होंने अपने अतिथियों के स्वागत और सत्कार में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। कई लोगों ने तमिलनाडु से आए अतिथियों के लिए अपने घरों के दरवाजे तक खोल दिए। स्थानीय प्रशासन भी चौबीसों घंटे जुटा रहा, ताकि मेहमानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वाराणसी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये गर्व और संतोष दोनों का विषय है। इस बार काशी-तमिल संगमम का समापन समारोह रामेश्वरम में आयोजित किया गया, जिसमें तमिलनाडु के सपूत उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी भी मौजूद रहे। उन्होंने इस कार्यक्रम को अपने विचारों से समृद्ध बनाया। भारतवर्ष की आध्यात्मिक समृद्धि पर बल देते हुए उन्होंने बताया कि कैसे इस तरह के मंच राष्ट्रीय एकता को और अधिक सुदृढ़ करते हैं। काशी-तमिल संगमम का बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिला है। इसके जरिए जहां सांस्कृतिक चेतना को मजबूती मिली है, वहीं शैक्षिक विमर्श और जनसंवाद को भी काफी बढ़ावा मिला है।

इससे हमारी संस्कृतियों के बीच संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। इस मंच ने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को आगे बढ़ाया है, इसलिए आने वाले समय में हम इस आयोजन को और वाइब्रेंट बनाने वाले हैं। ये वो भावना है जो शताब्दियों से हमारे पर्व-त्योहार, साहित्य, संगीत, कला, खान-पान, वास्तुकला और ज्ञान-पद्धतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। वर्ष का यह समय हर देशवासी के लिए बहुत ही पावन माना जाता है। लोग बड़े उत्साह के साथ संक्रांति, उत्तरायण, पोंगल, माघ बिहू जैसे अनेक त्यौहार मना रहे हैं। ये सभी उत्सव मुख्य रूप से सूर्यदेव, प्रकृति और कृषि को समर्पित हैं। ये त्यौहार लोगों को आपस में जोड़ते हैं जिससे समाज में सद्भाव और एकजुटता की भावना और प्रगाढ़ होती है। इस अवसर पर मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन उत्सवों के साथ हमारी साझी विरासत और सामूहिक भागीदारी की भावना देशवासियों की एकता को और मजबूत करेगी।

केंद्रित हिंसा अब भी लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती

14 जनवरी 2026 को दिल्ली में आयोजित पोंगल महोत्सव के मंच से भारतीय प्रधानमंत्री का यह कथन कि राष्ट्र निर्माण में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है,केवल एकसांस्कृतिक या औपचारिक वक्तव्य नहीं था, बल्कि यह भारत की आत्मा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना की ओर संकेत करने वाला राजनीतिक-वैचारिक संदेश था। पोंगल, जो कृषि, प्रकृति और श्रम के सम्मान का उत्सव है,उसी भारत का प्रतीक है जिसकी जड़ें खेतों में हैं। किंतु इसी कालखंड में प्रकाशित सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म (सीएसएसएस) की ताजा मॉनिटरिंग रिपोर्ट एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश करती है,जहाँ सांप्रदायिक दंगों में गिरावट के बावजूद मॉब लिंचिंग, नफरत आधारित अपराध और पहचान- केंद्रित हिंसा अब भी लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बने हुए हैं। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है,जिसकी सामाजिक संरचना बहुधर्मी बहुभाषी और बहु सांस्कृतिक ताने-बाने से निर्मित है। ऐसे समाज में सांप्रदायिक सौहार्द केवल आंतरिक स्थिरता का प्रश्न नहीं,बल्कि वैश्विक लोकतांत्रिक विश्व के लिए एक नैतिक और राजनीतिक संकेतक भी है, इसलिए, यह लेख इन्हीं दो समानांतर सच्चाइयों,आशा और चिंता,के बीच भारत के समकालीन सामाजिक- राजनीतिक परिदृश्य का अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह लेख सीएसएसएस की रिपोर्टिंग पर आधारित है इसकी सटीकता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। साथियों बात अगर हम कृषि और राष्ट्-निर्माण भारतीय सभ्यता की आधारशिला इसको समझने की करें तोभारत में कृषि केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत संरचना है। सिंधु घाटी से लेकर आधुनिक भारत तक, किसान समाज की स्थिरता, खाद्य सुरक्षा और सांस्कृतिक निरंतरता का मूल आधार रहा है। प्रधानमंत्री का पोंगल मंच से दिया गया वक्तव्य इसी ऐतिहासिक सत्य को पुनःरेखांकित करता है। वैश्विक संदर्भ में देखें तो आज जब विकसित देश भी खाद्य आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा मान रहे हैं,भारत का किसान-केंद्रित विमर्श उसे एक स्थायी विकास मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे एफएओ और विश्व बैंक भी मानती हैं कि भारत की कृषि व्यवस्थातमाम चुनौतियों के बावजूद,वैश्विक खाद्य संकट के दौर में एक स्थिर स्तंभ बनी हुई है। पोंगल केवल तमिल संस्कृति का पर्व नहीं,बल्कि यह श्रम, प्रकृति और समुदाय केसामूहिक उत्सव का प्रतीक है। जब प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति इस पर्व के माध्यम से किसानों को राष्ट्-निर्माण का नायक बताते हैं, तो यह संदेश केवल घरेलू नहीं बल्कि वैश्विक भी होता है। यह भारत को एक ऐसे देश के रूप में प्रस्तुत करता है जहां विकास का मॉडल जमीनी स्तर से जुड़ा है। किंतु यही समावेशी सांस्कृतिक संदेश तब कमजोर पड़ता है,जब समाज के भीतर पहचान- आधारित हिंसा और नफरत की राजनीति सामाजिक ताने-बाने को चोट पहुँचाती है। सीएसएसएस की 2025 की मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत में दर्ज बड़े सांप्रदायिक दंगों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है।यह एक सकारात्मक संकेत है और इसे कानून- व्यवस्था में सुधार,त्वरित प्रशासनिक हस्तक्षेप और न्यायिक सक्रियता से जोड़ा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तरपर यह भारत के लिए एक राहतकारी आंकड़ा है, क्योंकि लंबे समय से वैश्विक मानवाधिकार संगठनों द्वारा भारत में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। किंतु रिपोर्ट का दूसरा पक्ष अधिक चिंताजनक है हिंसा समाप्त नहीं हुई है, बल्कि उसने नए, अधिक विकेंद्रीकृत और अप्रत्याशित रूप धारण कर लिए हैं। मॉब लिंचिंग -भीड़ का उभार और राज्य की परीक्षा मॉब लिंचिंग आधुनिक लोकतंत्र की सबसे भयावह विफलताओं में से एक मानी जाती है। भारत में यह हिंसा अक्सर अफवाह,पहचान और सामाजिक पूर्वाग्रहों से प्रेरित होती है। सीएसएसएस रिपोर्ट बताती है कि 2025 में मॉब लिंचिंग की घटनाएँ भले ही बड़े दंगों की तरह सुर्खियों में न रही हों, लेकिन उनकी सामाजिक क्षति कहीं अधिक गहरी रही है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विमर्श में मॉब लिंचिंग को अनऑफिशियल जस्टिस सिस्टम के रूप में देखा जाता है, जहाँ राज्य की वैधता और कानून का शासन सीधे चुनौती के घेरे में आ जाता है।नफरत आधारित अपराध- वैश्विक प्रवृत्ति, भारतीय संदर्भ नफरत आधारित अपराध केवल भारत की समस्या नहीं हैं।अमेरिका यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में यह एक उभरती वैश्विक प्रवृत्ति है। किंतु भारत में इसकी जटिलता इस कारण बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पहचान, धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र, इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई है। सीएसएसएस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में नफरत अपराधों का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया से उपजी गलत सूचनाओं और राजनीतिक ध्रुवीकरण से जुड़ा रहा। यह स्थिति भारत के डिजिटल लोकतंत्र के लिए गंभीर चेतावनी है। पहचान-आधारित हिंसा और सामाजिक विखंडन पहचान- केंद्रित हिंसा का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह समाज को स्थायी रूप से विभाजित कर देती है। किसान, मजदूर और निम्न- आय वर्ग, जिनका राष्ट्- निर्माण में सबसे बड़ा योगदान है, वही वर्ग अक्सर ऐसी हिंसा का शिकार बनता है। यह विरोधाभास भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत,समानता और बंधुत्व को कमजोर करता है। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक मानते हैं कि यदि पहचान-आधारित हिंसा पर समय रहते नियंत्रण नहीं पाया गया, तो यह आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता दोनों को प्रभावित कर सकती है। साथियों बात अगर हम राज्य, नीति और नैतिक जिम्मेदारी इसको समझने की करें तो, प्रधानमंत्री का किसान- सम्मान संदेश तभी सार्थक होगा जब राज्य समान रूप से हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करे। सीएसएसएस रिपोर्ट अप्रत्यक्ष रूप से यह सवाल उठाती है कि क्या कानून का कार्यान्वयन हर स्तर पर निष्पक्ष है।अंतरराष्ट्रीय लोकतांत्रिक मानकों के अनुसार, हिंसा की रोकथाम केवल पुलिसिंग का विषय नहीं, बल्कि शिक्षा,सामाजिक संवाद और राजनीतिक जिम्मेदारी का भी प्रश्न है। भारत के लिए यह एक निर्णायक मोड़ है,या तो वह अपने विकास मॉडल को सामाजिक न्याय के साथ जोड़े, या फिर आर्थिक प्रगति के बावजूद सामाजिक असंतोष से जूझता रहे। साथियों बात अगर हम वैश्विक छवि और भारत की सॉफ्ट पावर इसको समझने की करें तो,भारत आज स्वयं को विश्व गुरु, ग्लोबल साउथ के नेता और लोकतांत्रिक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। किसान-केंद्रित सांस्कृतिक आयोजनों और विकासशील अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक सौहार्द इसकी सॉफ्ट पावर का अहम हिस्सा है। किंतु मॉब लिंचिंग और नफरत अपराधों की खबरें अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इस छवि को नुकसान पहुँचाती हैं। सीएसएसएस जैसी रिपोर्टें वैश्विक नीति- निर्माताओं और निवेशकों के लिए संकेतक बन जाती हैं। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि एक समग्र राष्ट्- निर्माण की आवश्यकता,14 जनवरी 2026 को पोंगल मंच से दिया गया प्रधानमंत्री का वक्तव्य भारत की आत्मा की आवाज़ है, एक ऐसा भारत जो किसान, श्रम और प्रकृति के सम्मान पर खड़ा है। किंतु सीएसएसएस की 2025 की रिपोर्ट यह याद दिलाती है कि राष्ट्-निर्माण केवल आर्थिक या सांस्कृतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और सुरक्षा की भी कसौटी है। जब तक किसान की मेहनत और नागरिक की सुरक्षा समान रूप से संरक्षित नहीं होंगी, तब तक भारत का राष्ट्-निर्माण अधूरा रहेगा। अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से भी भारत की सफलता इसी संतुलन में निहित है,विकास के साथ मानवीय गरिमा, और सांस्कृतिक गर्व के साथ सामाजिक सद्भाव।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने बन्ना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पैंचशीला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। ([illegible])

शायर मंसूर उस्मानी के घर में लगी आग, बेटी की हुई मौत, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा

मुरादाबाद।

अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर मंसूर उस्मानी के घर आग लग गई। इस हादसे में उनकी 40 वर्षीय बेटी हुमा उस्मानी की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गयी। आग लगने ही वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे से परिजनों में मातम छा गया। शायर मंसूर उस्मानी की बेटी की मौत की खबर से साहित्य जगत में भी शोक की लहर व्याप्त रही। शायर मंसूर उस्मानी का कोतवाली थाना अन्तर्गत बारादरी क्षेत्र के हम्माम वाली गली में मकान है। बताया जाता है कि मकान की ऊपरी मंजिल में उनकी बेटी हुमा उस्मानी ठहरी हुई थीं। ठंड होने की वजह से उन्होंने हीटर जला रखा था। बताया जाता है कि रात्री में किसी समय हीटर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। बताया गया कि आग इतनी तेजी से फैली कि हुमा को कमरे से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। परिजनों और आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि काबू पाना मुश्किल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक हुमा उस्मानी की मौत हो चुकी थी। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है और इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। हुमा उस्मानी का जनाजा आज दोपहर × बजे कचहरी वाले कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और घटना को प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से हुई दुर्घटना बताया है। सूचना मिलते ही मंसूर उस्मानी के साथी साहित्यकार, नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी उनके निवास पर पहुँच गए थे । हादसे के कारण लोगों में काफी दुख देखा जा रहा है। परिजन पूरी तरह से गमगीन हैं। मंसूर उस्मानी की बेटी के निधन पर सांसद रूचि वीरा, एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त, विधायक हाजी नासिर कुरैशी, पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी व हाजी यूसुफ अंसारी, कांग्रेस नेता मुहम्मद अहमद खान, असलम खुर्शीद, असद मौलाई के साथ ही सुशील कुमार शर्मा, हाजी अशरफ अली, डॉ. प्रदीप शर्मा, जाकिर अली बेग, मौआम अली वगैराह ने भी दुख ज़ाहिर किया है।

आयुष्मान योजनाः मुरादाबाद में 11.90 लाख लोगों को मिला सुरक्षा कवचः सीएमओ

मुरादाबाद।

गंभीर बीमारियों के लिए अब दिल्ली-लखनऊ की राह हुई आसान, पैसो की तंगी नहीं बन रही इलाज में बाधा

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के संकल्प का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। मुरादाबाद जिले में आयुष्मान भारत योजना न केवल बीमारों का सहारा बनी है, बल्कि हजारों परिवारों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। जिले में अब तक 11 लाख 90 हजार से अधिक लोग इस योजना के तहत अपना कार्ड बनवा चुके हैं, जिससे उन्हें सालाना 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। डॉ. कुलदीप सिंह, सीएमओ, मुरादाबाद ने बताया कि योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले के 102 निजी अस्पतालों और 29 सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों का प्राथमिकता के आधार पर इलाज किया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 1,90,488 लोगों ने निजी अस्पतालों में अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज कराया है, जबकि 17,084 मरीजों ने सरकारी अस्पतालों में इस योजना का लाभ उठाया है। माइनर सर्जरी, हड्डियों के ऑपरेशन और गाइनी (स्त्री रोग) से जुड़ी समस्याओं के लिए जिले में ही विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। बताया कि एक समय था जब मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्रों के लोग पैसों की तंगी के चलते अपने परिजनों का इलाज सही समय पर नहीं करा पाते थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आरोग्य विजन ने इस तस्वीर को बदल दिया है। अब जिले के मरीज सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि कैंसर और हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों के लिए दिल्ली, लखनऊ और चेन्नई के बड़े सूचीबद्ध अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज पा रहे हैं। लाभार्थियों का कहना है कि सरकार की इस योजना ने उनके परिजनों को नया जीवन दिया है। बताया कि प्रशासन ने जिले में 1× लाख 62 हजार 878 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसके सापेक्ष अब तक 11 लाख 90 हजार 927 कार्ड बनाए जा चुके हैं। जो लोग अभी भी इस सुविधा से वंचित हैं, उनके लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का नाम सरकारी सूची में होना और आधार कार्ड में सही उम्र दर्ज होना अनिवार्य है। मुरादाबाद में आयुष्मान योजना के तहत पात्रों को शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने के लिए हमारा विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जिले के 1×1 अस्पताल इस योजना से जुड़कर सेवा दे रहे हैं। हमारा प्रयास है कि कोई भी जरूरतमंद इलाज के अभाव में न रहे। विशेष अभियान के जरिए हम उन लोगों तक भी पहुंच रहे हैं जिनके कार्ड अभी तक नहीं बन पाए हैं।

टीकाकरण में सहयोग देने पर धर्मगुरूओं का हुआ सम्मान

मुरादाबाद। गावी जीरो डोज कार्यक्रम परियोजना के तहत जनपद स्तरीय धर्म गुरु बैठक का आयोजन यूनिसेफ पीसीआई एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा होटल मिड टाउन मुरादाबाद में आयोजित किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य टीकाकरण को प्रभावी बनाने के लिए एवं सभी धर्म गुरुओं का टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए उनको डिप्टी सीएम डॉक्टर संजीव बेलवाल ने सभी धर्म गुरुओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। पीसीआई यूनिसेफ की ओर से एक धार्मिक गुरुओं का आयोजन किया गया धर्मगुरु बैठक में उपस्थित शहर इमाम सैयद फहद अली, गुरविंदर सिंह, पंडित राघव शर्मा ,डेनियल मसीह, कारी अख्तारुल इस्लाम व समाज सेवी फ़िरोज़ खां, जनपद से आए धर्मगुरु को सम्मान पत्र देकर डिप्टी सीएम डॉक्टर संजीव बेलवाल ,डॉक्टर सुरजीत सिंह डिविजनल हेल्थ कोऑर्डिनेटर, मोहम्मद शमी खान रीजनल कोऑर्डिनेटर यूनिसेफ ,अर्बन हेल्थ कोऑर्डिनेटर प्रमोद कुमार द्वारा सभी को सम्मानित किया गया बैठक का मुख्य उद्देश्य 1 साल तक जिस ब'चे को बुनियादी एवं काली खांसी गलाघोट,टेटनेस का कोई भी टीका नहीं लगता उन ब'चों को और परिवार को प्रेरित कर टीकाकरण कराने के लिए इन सभी धर्म गुरुओं ने स्वास्थ्य विभाग को जो सहयोग किया उस उपलक्ष में आज बैठक का आयोजन किया गया था।

बैठक में उपस्थित डब्लूएचओ अंजार अली , जे एस आई से राबिया खान स्वास्थ्य विभाग से उर्वा दत्त तिवारी ,शाहनवाज हुसैन ,प्रमोद कुमार एवं जनपद से अलग-अलग क्षेत्र से आए सभी धर्म गुरुओं ने बैठक में भाग लिया। बैठक का संचालन मोहम्मद जावेद अख्तर सीएसओ कॉर्डिनेटर पीसीआई मुरादाबाद द्वारा किया गया बैठक में सहयोग रफीक अहमद, रीना यादव, गीता रानी, तरन्नुम निशा और मोहम्मद सलमान, द्वारा किया गया।

टीएमयू में लोहड़ी पर खूब थिरके मेडिकल कॉलेज के

मकर संक्रांति पर स्टुडेंट्स के संग-संग गुरूजनों ने भी उड़ाई पतंग, सीसीएसआईटी में भी रही लोहड़ी की धूम

मुरादाबाद।

तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के हॉस्टल्स और कैंपस के अलावा तीर्थंकर महावीर डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, सीसीएसआईटी सरीखे कॉलेजों में लोहड़ी और मकर संक्रांति के पर्व पारम्परिक तरीके से मनाए गए।

इनमें स्टुडेंट्स की सर्वाधिक भागीदारी रही। मेडिकल कॉलेज के ब्वॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और ओल्ड गर्ल्स हॉस्टल में लोहड़ी का त्यौहार उत्साह के संग मनाया गया। लोहड़ी प्रज्जवलन के बाद स्टुडेंट्स ढोल की थाप पर लोहड़ी के गानों पर खूब थिरके। स्टुडेंट्स ने तिल, गुड़, मूंगफली, पॉपकॉर्न आदि पारंपरिक वस्तुएं लोहड़ी को अर्पित कीं। लोहड़ी अनुष्ठान के संग-संग सामूहिक मिलन का पर्व भी है। टीएमयू हॉस्टल्स में बड़ी संख्या में पंजाबी छात्र-छात्राएं रहते हैं। लोहड़ी पर डॉ. करुणा जैन के संग-संग प्रो. प्रीथपाल सिंह मटरेजा, प्रो. सीमा अवस्थी, प्रो. अमित सराफ, डॉ. आशुतोष, डॉ. रत्नेश जैन, डॉ. नम्रता जैन, डॉ. मधुसूदन आदि की उल्लेखनीय मौजूदगी रही। लोहड़ी में एमबीबीएस के स्टुडेंट्स- रोहिन अग्रवाल, आकाश पुरी, वेद प्रकाश, राहुल कुमार, दिव्यांश मेहरोत्रा आदि की भी भागीदारी रही, गर्ल्स हॉस्टल्स की ओर से लोहड़ी पर मेडिकल की छात्राओं- अर्शदीप कौर, हिमांशी कौर, आन्या जैन, सुष्मिता यादव, सोनम कुमारी, स्नेहा श्रीवास्तव, तनु कुमारी ने जमकर नृत्य किया। तीर्थंकर महावीर डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में मकर संक्रांति पर न केवल स्टुडेंट्स बल्कि गुरूजनों ने भी रंग-बिरंगी पतंग उड़ाई। डेंटल कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल डॉ. अंकिता जैन ने कहा, मकर सक्रांति सरीखे आयोजन से स्टुडेंट्स में टीम भावना, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। इस मौके पर डेंटल के प्रिंसिपल प्रो. प्रदीप तांगड़े, डॉ. विकास सिंह, डॉ. दीपक ठाकुर, डॉ. सिवान सतीश, डॉ. कार्तिकेय सक्सेना, डॉ. अभिनय अग्रवाल, डॉ. सौभाग्य अग्रवाल, डॉ. जैनुअल, डॉ. शुभम मिश्रा आदि की मौजूदगी रही। स्टुडेंट्स को रेवड़िया बांटकर मुंह मीठा कराया गया। इसके अलावा सीसीएसआईटी में भी लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सीसीएसआईटी में डीन प्रो. आरके द्विवेदी, प्रो. शंभू भारद्वाज, डॉ. संदीप वर्मा, नवनीत विश्नोई, 'योति रंजन लाभ, हरजिंदर सिंह, अनुज राघव, शिखा गंभीर आदि मौजूद रहे। एक-दूसरे को लोहड़ी की बधाई देते हुए मूंगफली, रेवड़ी, गजक आदि का वितरण किया गया।

आज से शुरू होंगी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं

मुरादाबाद । गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलपति प्रो. सचिन माहेश्वरी ने बताया कि परीक्षा की शुचिता बनाये रखने के लिये हर संभव प्रयास किये जायेंगे। परीक्षार्थी किसी भी कीमत पर अनुचित साधनों का प्रयोग न करें। नकल विहीन परीक्षाएं सम्पन्न कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। प्रेसवार्ता के दौरान कुलपति प्रो. सचिन माहेश्वरी ने बताया कि गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय की स्नातक और परास्नातक परीक्षाएं शुक्रवार, 16 जनवरी से शुरू हो रही हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन परीक्षाओं के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। छात्रों के एडमिट कार्ड बुधवार को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिन्हें वे डाउनलोड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार, छात्रों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। 15 मिनट से अधिक देरी से पहुंचने वाले छात्रों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। स्नातक की परीक्षाएं 16 जनवरी से 16 फरवरी तक चलेंगी, जिसके लिए कुल 158 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें मुरादाबाद में 40, बिजनौर में 52, रामपुर में 21, संभल में 22 और अमरोहा में 2× परीक्षा केंद्र शामिल हैं। परास्नातक की परीक्षाएं भी 16 जनवरी से शुरू होकर 12 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं तीन पालियों में होंगी। पहली पाली सुबह 9 से 11 बजे तक, दूसरी पाली दोपहर 12 से 2 बजे तक और तीसरी पाली दोपहर × से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। कुलपति प्रो. सचिन माहेश्वरी ने बताया कि सभी स्नातक और परास्नातक परीक्षाएं शांतिपूर्ण एवं नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

बसपाईयो ने हर्षोल्लास के साथ मनाया बहन जी का जन्मदिन

मुरादाबाद।

बहन कुमारी मायावती (राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा/पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश/पूर्व सांसद रा'यसभा/ लोकसभा) का जन्मदिन जनकल्याणकारी दिवस के रूप में डॉ.भीमराव अंबेडकर पार्क सिविल लाइंस मुरादाबाद में मनाया गया, जिसमें गिरीश चंद्र (पूर्व सांसद नगीना/ प्रभारी उत्तराखंड /मुख्य सेक्टर प्रभारी मुरादाबाद मंडल) ने डॉ.भीमराव अंबेडकर पार्क सिविल लाइंस मुरादाबाद में पहुंचकर भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बताया कि अगर आप आज असली तोहफा बहन जी को देना चाहते हैं

सीएम बनाने का लिया संकल्प

तो आपको इस बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन जी को बनाना होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जाफर मलिक (मुख्य सेक्टर प्रभारी मुरादाबाद/ अलीगढ़/मेरठ मंडल) ने बहन जी के पूरे जीवन संघर्ष और त्याग एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब के जीवन संघर्ष पर पूरा प्रकाश डाला, और बताया कि बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में चार- बार सरकार रही, आदरणीय बहन जी ने अपनी चारों

सरकारों में बतौर मुख्यमंत्री बिना भेदभाव सर्व समाज के लोगों का काम किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता- डॉ.रणविजय सिंह एडवोकेट (मुख्य सेक्टर प्रभारी मुरादाबाद मंडल) ने की और बताया कि अगर आप बहन जी को असली तोहफा देना चाहते हैं तो आपको 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी

कार्यक्रम का संचालन -निर्मल सिंह सागर एडवोकेट (जिला अध्यक्ष मुरादाबाद) ने किया और लोगों का आभार और धन्यवाद देते हुए बताया कि प्रदेश के 85 प्रतिशत लोगों को आज यह संकल्प लेना होगा कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमों बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का 5 वीं बार मुख्यमंत्री बनना है।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से,सेक्टर प्रभारी मुरादाबाद मंडल अमर सिंह, अरुण कुमार टिंकू, फैसल रज़ा असारी, गजेंद्र सिंह, वेद प्रकाश, सुनील आज़ाद एडवोकेट, शिव शंकर सागर एडवोकेट, जिला संयोजक भाईचारा चंद्रपाल सिंह सैनी, ऋषिपाल सिंह प्रधान एडवोकेट,हाजी शकील अहमद जिला उपाध्यक्ष राधेश्याम पाल (जिला महासचिव), करतार सिंह (जिला सचिव) सदस्य जिला कार्यकारिणी राजेश सागर, श्री पवन कश्यप, इरफान सैफी एडवोकेट पूर्व प्रत्याशी लोकसभा मुरादाबाद , इरशाद सैफी एडवोकेट पूर्व प्रत्याशी नगर विधानसभा, अखिल चौधरी पूर्व प्रत्याशी देहात विधानसभा मुकेश कुमार, भयंकर सिंह, मुनेश पाल,लोकेश कुमार, राकेश कुमार, शिवलाल,सुरेंद्र फौजी अरुण कुमार रिंटू, जितेंद्र जाटव,बंटी भारती, भूप सिंह, चमन सिंह, मनवीर सिंह रन सिंह भारती डॉ.चरन सिंह, एवं मुरादाबाद मंडल के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे।

काजू के डिब्बों में छिपाकर हो रहा था गांजा तस्करी, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने तीन तस्करों को दबोचा

नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच ने एक बड़े अंतरराज्यीय गांजा सिंडिकेट के तीन तस्करों सोनू, अजीत और रुद्रप्रताप उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया है। आरोपी काजू के डिब्बों में छिपाकर गांजे की खेप की तस्करी करते थे और कूरियर सर्विस के जरिए दिल्ली भेजते थे। पिछले एक साल में उन्होंने ओडिशा से 5,000 किलोग्राम गांजा मंगवाया था और दिल्ली-एनसीआर में बेचा था। उनके पास से 165.74 किलोग्राम गांजा, तीन मोबाइल फोन और दो स्कूटर जब्त किए गए। यह गांजा दिल्ली-एनसीआर में छोटे तस्करों को सप्लाई किया जाना था। मुख्य गांजा सप्लायर को ओडिशा में गिरफ्तार किया गया। डीसीपी क्राइम ब्रांच पंकज कुमार के अनुसार, गिरफ्तार किए गए तस्कर सोनू, खिचड़ीपुर, अजीत, ज्वालापुरी और रुद्रप्रताप हैं, ये सभी ओडिशा के रहने वाले हैं। रुद्रप्रताप ने पिछले एक साल में दिल्ली में लगभग 5,000 किलोग्राम गांजा सप्लाई किया था। 24 दिसंबर को एक मुखबिर ने क्राइम ब्रांच को सूचना दी कि सोनू और अजीत नाम के तस्कर मंगोलपुरी में गांजे की खेप लेने वाले हैं। इंस्पेक्टर योगेश माथुर और विनोद यादव के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने रात 9 बजे मंगोलपुरी में एक स्कूटर पर तीन कार्टन ले जा रहे एक व्यक्ति को देखा। थोड़ी देर बाद, एक और व्यक्ति दूसरे स्कूटर पर आया और कार्टन शिफ्ट करने लगा। बिना समय गंवाए, पुलिस टीम ने दोनों स्कूटर सवारों को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उनकी पहचान खिचड़ीपुर के रहने वाले सोनू और ज्वालापुरी के रहने वाले अजीत के रूप में हुई। दोनों स्कूटरों की तलाशी लेने पर तीन कार्टन बरामद हुए, जिनमें से प्रत्येक में 15 पैकेट थे। जांच करने पर, एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया और 47.34 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान, अजीत ने बताया कि गांजा ओडिशा के रहने वाले रुद्रप्रताप ने भेजा था। इसलिए, अजीत को पुलिस रिमांड पर ओडिशा ले जाया गया, क्योंकि बरामद गांजा ओडिशा से एक बड़ी कूरियर सर्विस के जरिए भेजा गया था। ओडिशा में कूरियर कंपनी के मैनेजर ने बताया कि रुद्रप्रताप नाम के एक व्यक्ति ने सात डिब्बों की खेप दिल्ली भेजी थी। इस जानकारी के आधार पर अजीत से और पूछताछ की गई। उसने बताया कि सात डिब्बे दिल्ली में एक कूरियर कंपनी के ऑफिस में पड़े हैं। इसके बाद, अजीत की जानकारी के आधार पर दिल्ली से 118.4 किलोग्राम गांजा और बरामद किया गया, जिससे कुल बरामदगी 165.74 किलोग्राम हो गई। पूछताछ में पता चला कि रुद्रप्रताप गांजे का मुख्य सोर्स था। पुलिस टीम तुरंत ओडिशा गई और लगभग तीन हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद, टेक्निकल सर्विलांस और मैनुअल सोर्स के आधार पर उसे ओडिशा के पुरी में गिरफ्तार कर लिया। अजीत दिल्ली ड्रग सिंडिकेट का सरगना है, जो गांजे के मुख्य सोर्स रुद्रप्रताप के रेगुलर संपर्क में था। रुद्रप्रताप काजू के डिब्बों में छिपाकर कूरियर सर्विस से गांजे की खेप दिल्ली भेजता था। अजीत से एडवांस पेमेंट मिलने के बाद, पप्पू मुअर कूरियर सर्विस से खेप दिल्ली भेजता था। आरोपी खेप की आवाजाही और डिलीवरी को कोऑर्डिनेट करने के लिए लीगल कूरियर चैनलों का इस्तेमाल करते थे और रियल-टाइम ट्रैकिंग अपडेट और मैसेज-बेस्ड निर्देशों पर निर्भर रहते थे। दिल्ली पहुंचने पर, अजीत ने पुलिस की नजर से बचने के लिए जानबूझकर खुद डिलीवरी लेने से परहेज किया और इसके बजाय अपने मजदूर सोनू को मंगोलपुरी इलाके में खेप लेने के लिए भेजा।

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर पर लगाई रोक

I-PAC छापेमारी मामले में ममता सरकार को झटका

नई दिल्ली। जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगा दी है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने I-PAC ऑफिस में रेड करने पर ईडी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बंगाल सरकार से कहा कि एजेंसी के काम में दखल नहीं दे सकते.

ममता सरकार से दो हफ्तों में मांग जवाब

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने सीसीटीवी फुटेज समेत सभी सबूतों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस और पुलिस को नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 को होगी. कोर्ट ने ममता सरकार से दो हफ्तों के भीतर जवाब मांगा और कहा कि केंद्रीय एजेंसी के आरोप गंभीर है.

ममता बनर्जी पर सबूत चोरी के आरोप

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 8 जनवरी 2026 को रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंचीं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज अपने साथ ले गईं. ममता के साथ बंगाल डीजीपी भी पुलिस टीम के साथ पहुंचे थे. पुलिस ने ईडी अफसरों के मोबाइल छीन लिए, ममता बनर्जी मीडिया के सामने भी गईं. इस तरह ईडी का मनोबल गिरता है और उनके काम में बाधा आती है. सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, ममता बनर्जी आरोपी हैं और उन्होंने डीजीपी की मिलीभगत से सबूतों की चोरी की. अगर बंगाल में किसी एफआईआर की जांच होती है तो कुछ नहीं होगा. इसलिए मामले में सीबीआई जांच की जरूरत है.

कपिल सिब्बल पर फूटा बेंच का गुस्सा

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम हाईकोर्ट के रवैये से बहुत परेशान हैं. वहीं, कपिल सिब्बल ने कहा कि कल सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट को यह मानना होगा कि हाईकोर्ट न्याय देने में असमर्थ है. सिब्बल की इस बात पर बेंच ने गुस्से में कहा, आप मेरे मुंह में शब्द नहीं डाल सकते. हम फैसला करेंगे कि हमें क्या मानना है और क्या नहीं.

मुंबई में बीजेपी का परचम!

बीएमसी एग्जिट पोल में महायुति को 150+ सीटें, ठाकरे का किला ढहने के संकेत

मुंबई। महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों, जिनमें बीएमसी भी शामिल है, के लिए मतदान समाप्त होने के बाद, अब सभी की निगाहें चुनाव परिणाम के अनुमानों पर टिकी है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के 227 वार्डों में मतदान संपन्न हो चुका है।

एग्जिट पोल के अनुसार, महायुति गठबंधन को भारी जीत मिलने की संभावना है। जेवीसी एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक, महायुति गठबंधन को 138 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन को 59 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के अनुसार, कांग्रेस को 23 सीटें और अन्य दलों को 7 सीटें मिलने की संभावना है। एक्सिस माई इंडिया के अनुमानों में बीएमसी में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए भारी जीत दिखाई गई है, जिसमें महायुति को 131-151 सीटें मिल रही हैं, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गठबंधन को 58-68 सीटें मिल रही है। एक्सिस माई इंडिया के चुनावोत्तर अनुमानों के अनुसार, भाजपा 28फीसदी वोटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 14फीसदी और उद्धव की शिवसेना को 24फीसदी वोट मिले है। पार्टीवार वोट शेयर की बात करें तो भाजपा- 28फीसदी, एसएस (शिंदे)- 14फीसदी, यूबीटी- 24फीसदी, एमएनएस- 7फीसदी, एनसीपी (एसपी)- 1फीसदी, कांग्रेस-वीबीए-आरएसपी- 13फीसदी और अन्य- 13फीसदी मिल सकती है। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए मतदान गुरुवार शाम 5:30 बजे समाप्त हो गया। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बताया कि अब तक मतदान प्रतिशत 46-50 प्रतिशत के बीच रहा है। वाघमारे ने कहा कि इस बार का मतदान 2017 के नगर निगम चुनावों से अधिक है और वे मतदान प्रतिशत से संतुष्ट हैं। एसईसी के आंकड़ों के अनुसार, राज्य भर में दोपहर 3:30 बजे तक 41.13 प्रतिशत मतदान हुआ था। बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए सकल एग्जिट पोल के अनुसार, भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन 227 सदस्यीय नगर निकाय में 119 सीटों के साथ सबसे बड़ा गठबंधन बनने की ओर अग्रसर है। शिवसेना (यूबीटी) के नेतृत्व वाले गठबंधन को 75 सीटों के साथ मजबूत प्रदर्शन करने की उम्मीद है। कांग्रेस को लगभग 20 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य दलों को 14 सीटें मिलने की संभावना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोलते हुए, शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने मुंबई नगर आयुक्त भूषण गगरानी और कमलाबाई के बीच हुई «लंबी चर्चा» पर सवाल उठाते हुए बैठक के नतीजों पर सवाल उठाए। राउत ने आरोप लगाया कि इस बातचीत में देवेंद्र फडणवीस के «मुंबई स्थित विशेष कोषाध्यक्ष» और एक पसंदीदा बिल्डर शामिल हो सकते हैं, और पूछा कि बंद कमरे में हुई बातचीत में आखिर क्या निर्णय लिए गए।

कोल्लम में एसएआई हॉस्टल में दो युवा महिला एथलीटों की दुखद मौत

केरल के कोल्लम जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। गुरुवार सुबह (15 जनवरी) भारतीय खेल प्राधिकरण के महिला हॉस्टल में दो होनहार ट्रेनी एथलीटों के शव उनके कमरे में फंदे से लटके पाए गए। इस घटना के बाद खेल जगत और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर इसे आत्महत्या का मामला मानकर जांच शुरू कर दी है। गुरुवार सुबह (15 जनवरी) को केरल के कोल्लम में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महिला हॉस्टल में दो टीनएजर स्पोर्ट्स ट्रेनी एक कमरे में फंदे से लटकी मिलीं, जिसके बाद पुलिस ने आत्महत्या की आशंका में जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान कोझिकोड जिले की 17 साल की एथलेटिक्स की ट्रेनिंग ले रही छात्रा सैंड्रा और तिरुवनंतपुरम जिले की 15 साल की 10वीं क्लास की छात्रा वैष्णवी के रूप में हुई है, जो कबड्डी में माहिर थी। दोनों SAI हॉस्टल में रहती थी और उसके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा थीं।

अकाल तख्त के समक्ष पेश हुए मुख्यमंत्री मान, गोलक बयान पर दी सफाई, कहा- हर फैसला मंजूर

पंजाब।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को सिख परंपराओं पर कथित टिप्पणियों के संबंध में श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश हुए और उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ फैलाई जा रही अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। सचिवालय के समक्ष पेश होने के बाद उन्होंने कहा कि तख्त साहिब का निर्णय उन्हें सूचित किया जाएगा और वे इस निकाय के आगामी निर्णय का सम्मान करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके बयान का वीडियो फर्जी है और उन्होंने इसे फॉरेंसिक प्रयोगशाला में जांच कराने का प्रस्ताव रखा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ मिली सभी शिकायतों के जवाब में मैंने श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष अपना पक्ष रखा है। मैंने अकाल तख्त साहिब के समक्ष लिखित सबूत भी पेश किए हैं। मैंने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर चल रही ये अफवाहें कि भगवंत मान श्री अकाल तख्त साहिब को चुनौती दे रहे हैं, झूठी हैं। अकाल तख्त साहिब के समक्ष ऐसा करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। सिंह साहब का फैसला मुझे बता दिया जाएगा।

सिंह साहब के फैसले का सम्मान किया जाएगा... मैंने उन्हें बताया कि वीडियो फर्जी है और इसकी जांच किसी भी फॉरेंसिक प्रयोगशाला में कराई जा सकती है। इससे पहले, श्री अकाल तख्त साहिब के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) के अनुसार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान «गोलक» मुद्दे पर अपनी टिप्पणी के संबंध में अकाल तख्त साहिब सचिवालय के समक्ष पेश होने के लिए स्वर्ण मंदिर पहुंचे।

श्री अकाल तख्त साहिब के जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक, सचिवालय में जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज और तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी टेक सिंह के समक्ष मुख्यमंत्री की पेशी के दौरान जत्थेदारों ने सिख आचार संहिता से संबंधित मासिक गुरुद्वारा गजट पत्रिका की एक प्रति और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के पत्र उन्हें भेंट किए। मंगलवार को, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि गुरु की गोलक के खिलाफ कथित बयानों के लिए तलब किए जाने के बाद उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेशी के समय में बदलाव की मांग नहीं की थी। भगवंत मान ने एक पोस्ट में कहा कि वह श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा मांगे गए अनुसार 15 जनवरी को सुबह 10 बजे उपस्थित होने के लिए तैयार हैं।

जत्थेदार को दिया स्पष्टीकरण, कहा-मैंने कभी श्री अकाल तख्त को चैलेंज नहीं किया

मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास को लेकर पीएम मोदी पर बरसे खरगे, ऐतिहासिक धरोहर मिटाने का आरोप

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को वाराणसी के प्रसिद्ध श्मशान घाट, मणिकर्णिका घाट के प्रस्तावित रूपांतरण पर सवाल उठाते हुए इसे बेरुखाद सौंदर्यीकरण और व्यवसायीकरण का प्रयास बताया, जो सदियों पुरानी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को नष्ट कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर कई मंदिरों, छोटे-बड़े तीर्थस्थलों को ध्वस्त किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खरगे ने पूछा कि लाखों लोग हर साल अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में मोक्ष की तलाश में काशी आते हैं। क्या आपका इरादा इन श्रद्धालुओं के साथ विश्वासघात करने का है? खरगे ने कथित तौर पर ध्वस्त की गई मूर्तियों और बुलडोजरों की तस्वीरें और वीडियो एक्स पर साझा किए। खरगे ने एक्स पर लिखा कि बेरुखाद सौंदर्यीकरण और व्यवसायीकरण के नाम पर आपने बनारस के मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाकर सदियों पुरानी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को नष्ट कर दिया है। आप चाहते हैं कि ऐतिहासिक विरासत का हर टुकड़ा मिटा दिया जाए और उस पर सिर्फ आपकी नामपट्टिका चिपका दी जाए। खरगे ने कहा कि गुप्त काल में स्थापित और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनर्निर्मित इस दुर्लभ धरोहर को ध्वस्त करना एक अपराध है। उन्होंने पूछा कि क्या इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी के «व्यापारिक मित्रों» को लाभ पहुंचाने का इरादा है? कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा कि आपने पानी, जंगल, पहाड़ - सब कुछ उन्हें सौंप दिया; अब सांस्कृतिक धरोहर की बारी है। देश की जनता के आपसे दो सवाल है - क्या धरोहर को संरक्षित करते हुए जीर्णोद्धार, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण नहीं किया जा सकता था? 2. मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर की चपेट में आने वाली सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियों पर कुल्हाड़ी क्यों चलाई गई और उन्हें मलबे में क्यों फेंक दिया गया? क्या उन्हें किसी संग्रहालय में संरक्षित नहीं किया जा सकता था? मणिकर्णिका घाट के जीर्णोद्धार और पुनर्विकास की योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 जुलाई, 2023 को आधारशिला रखने के साथ हुई थी। इस परियोजना की कुल जीर्णोद्धार लागत लगभग 17.56 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। नए मणिकर्णिका घाट की छत पर विशेष अतिथियों के लिए बैठने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा, रैंप, दर्शन क्षेत्र, बैठने की व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मणिकर्णिका घाट पर एक लकड़ी का प्लाजा भी बनाया जाएगा, जहां शोक संतप्त लोग अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी खरीद सकेंगे।

भारत ने जन केंद्रित नीतियों, कल्याण केंद्रित कानूनों से लोकतंत्र को मजबूत किया : बिरला

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व ऐसे समय में वैश्विक चुनौतियों का निर्णायक समाधान दे रहा है, जब दुनिया नेतृत्व के लिए उनकी ओर देख रही है।

संविधान सदन (पुराने संसद भवन) के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में राष्ट्रमंडल देशों की संसद के स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए, बिरला ने कहा कि भारत को सात दशक से अधिक लंबी संसदीय यात्रा में, लोगों पर केंद्रित नीतियों और कल्याण केंद्रित कानूनों के जरिए लोकतंत्र मजबूत हुआ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तटस्थ और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था ने सभी पात्र नागरिकों के लिए भागीदारी वाला लोकतंत्र सुनिश्चित किया है। बिरला ने कहा कि संसद और सरकार के सामूहिक प्रयासों से कई (अब तक 1500 से अधिक) अवांछित और पुराने कानूनों को रद्द किया गया है और जन कल्याण पर केंद्रित नए कानून बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कानूनों और नीतियों को लागू करने से भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित देश बनाने में मदद मिलती है।

उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ और सबूत देना चाहती है पीड़िता, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा

नई दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर निष्कासित भाजपा नेता व पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ मामले में अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति मांगी है। सेंगर को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसकी अपील फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़िता की इस याचिका पर सीबीआई और कुलदीप सिंह सेंगर से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने गुरुवार को इस आवेदन पर प्रारंभिक सुनवाई की। पीड़िता की ओर से वकील महमूद प्राचा ने अदालत में दलील दी कि उनकी मुवक्किल मामले में अपनी उम्र से संबंधित दस्तावेजों सहित कुछ अतिरिक्त सबूत पेश करना चाहती है। हालांकि, पीठ ने नोट किया कि ये दस्तावेज याचिका के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं। अदालत ने पीड़िता के वकील को निर्देश दिया कि वे 31 जनवरी तक सभी संबंधित दस्तावेज दाखिल करें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को तय की है। वहीं, सीबीआई और कुलदीप सिंह सेंगर को दो सप्ताह के भीतर इस आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा को उसकी अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया था, लेकिन 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी।

इस मामले में सेंगर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन अदालत में पेश हुए। इससे पहले तिस हजारी कोर्ट ने उन्नाव के नाबालिग दुष्कर्म मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्नाव से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था।

बदलाव लाने में जनभागीदारी महत्वपूर्ण है : सीएम उमर अब्दुल्ला

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि बदलाव लाने के लिए जनभागीदारी महत्वपूर्ण है और इसकी शुरुआत नागरिकों के मतदान के लिए बाहर निकलने से होती है। अब्दुल्ला ने पत्रकारों से कहा, ''बदलाव केवल वही लोग ला सकते हैं जो इसमें भाग लेने के लिए तैयार हों। भाग लेने का मतलब यह नहीं है कि मैं उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो जाऊं। भाग लेने का मतलब यह भी होता है कि मैं कम से कम बाहर आकर अपने वोट का इस्तेमाल करूं।'' अब्दुल्ला मुंबई के 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज' (आईआईसीटी) में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने आये थे। अब्दुल्ला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान आवश्यक है। अब्दुल्ला ने कहा कि चाहे जम्मू-कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो या मुंबई, लोगों की अपनी-अपनी समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि जब नतीजे आएंगे तो वोट ही भविष्य का फैसला करेंगे।

ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालेगी सरकार

आज से शुरू हो सकता है वतन वापसी का अभियान

नई दिल्ली। ईरान में पिछले 15 दिनों से जारी हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के चलते स्थिति बेहद ही भयावह हो गई है। भारत सरकार ईरान में फंसे नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, भारत सरकार ने नागरिकों को वापस लाने के लिए शुक्रवार से अभियान शुरू कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, विदेश मंत्रालय ईरान में मौजूदा अस्थिर स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और उन भारतीय नागरिकों की घर वापसी की सुविधा प्रदान करने के लिए व्यापक तैयारियां कर रहा है जो भारत लौटने के इच्छुक हैं। ईरान में पिछले 15 दिनों से विरोध प्रदर्शनों और हिंसा का सिलसिला जारी है, जिसने वहां की आंतरिक स्थिति को अत्यंत गंभीर बना दिया है। रिपोर्टों के अनुसार, सुरक्षा की दृष्टि से स्थिति अब भयावह स्तर तक पहुंच गई है। इससे वहां रह रहे विदेशी नागरिकों, विशेषकर भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस उभरती हुई परिस्थिति को देखते हुए, केंद्र सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर अपने नागरिकों को वहां से निकालने की योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ईरान में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए शुक्रवार से एक विशेष अभियान की शुरुआत कर सकती है। विदेश मंत्रालय वर्तमान में उन नागरिकों का डेटा और विवरण जुटाने और व्यवस्था करने की प्रक्रिया में है जो वर्तमान परिस्थितियों के कारण भारत वापस आने की इच्छा रखते हैं।

कल सरकार ने भारतीयों को देश छोड़ने की दी थी सलाह

बुधवार को तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने के लिए कहा था। दूतावास ने सोशल मीडिया पर जारी एक सलाह में कहा, ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों (छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों) को वाणिज्यिक उड़ानों सहित उपलब्ध किसी भी परिवहन साधनों का उपयोग करके ईरान छोड़ने की सलाह दी जाती है।

दूतावास की सलाह

भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी।

प्रदर्शन और अशांति वाले इलाकों से दूर रहने का स्पष्ट निर्देश। भारतीय नागरिकों से दूतावास के लगातार संपर्क में बने रहने की अपील। किसी भी नए घटनाक्रम की जानकारी के लिए स्थानीय मीडिया पर नजर रखने को कहा गया। पासपोर्ट, पहचान पत्र और अन्य यात्रा व आव्रजन दस्तावेज हर समय तैयार और अपने पास रखने की सलाह।

हेल्पलाइन नंबर जारी

दूतावास ने आपातकालीन संपर्क हेल्पलाइन भी जारी की है। इसके तहत मोबाइल नंबर +989128109115; +989128109109; +989128109102; +989932179359 और ईमेल- cons.tehran@mea.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

दूतावास में पंजीकरण कराएं भारतीय

सलाह में कहा गया है, ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक, जिन्होंने भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे https://www.meaers.com/request/home पर पंजीकरण कराएं। यह लिंक दूतावास की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

यदि ईरान में इंटरनेट की समस्या के कारण कोई भारतीय नागरिक पंजीकरण कराने में असमर्थ है, तो भारत में उनके परिवार से अनुरोध है कि वे पंजीकरण कराएं।